राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

RNI NO - UPHIN/2022/86937

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष – 03 | अंक – 322 | जौनपुर | शनिवार, 12 जलाई 2025 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज – 4 | मूल्य – 2 रूपये

राम विरोधियों की दुर्गति होनी तय है : योगी

लखनऊ, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी (सपा) पर निशाना साधते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि जो भी राम विरोधी है, उसकी दुर्गति होनी तय है। योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा के पर्व पर गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन में आयोजित महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सपा पर निशाना साधते हुए समाजवाद के प्रणेता कहे जाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जिक्र किया और कहा, ''प्रखर समाजवादी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी कहते थे कि भारत में जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान

श्रीराम, लीला पुरुषोत्तम मुरलीधर भगवान श्रीकृष्ण और देवों के देव भगवान शंकर की पूजा होती रहेगी तब तक दुनिया में कोई माई का लाल भारत का बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। डॉक्टर लोहिया के वर्तमान चेले (सपा नेता) भले ही उनकी बात न मानते हों लेकिन यह बात तय है कि जो राम विरोधी है, उसकी दुर्गति होनी ही है।'' मुख्यमंत्री ने कहा,''डॉक्टर लोहिया स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रखर समाजवादी और कांग्रेस के प्रखर विरोधी थे। आजादी के बाद जब भारतीयों की एकजुटता को लेकर कुछ लोगों ने शंका जताई थी तब उन्होंने जवाब दिया था कि राम, कृष्ण और शंकर की पूजा होने तक भारत की एकजुटता का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता।'' उन्होंने 1990 में तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाये जाने की घटना की तरफ इशारा करते हुए कहा,''प्रखर समाजवादी लोहिया के विचार से इतर आज के समाजवादी रामभक्तों पर गोली चलाते हैं।'' योगी आदित्यनाथ ने कहा,''उच्चकुल में पैदा होने के बावजूद मारीच की दुर्गति सबको पता है। उसका जन्म मनुष्य रूप में होता है जबकि पशु रूप में मारा जाता है।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का मेघालय का चार दिवसीय दौरा शुरू

नई दिल्ली, (एजेंसी)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को मेघालय की अपनी चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा की शुरुआत शिलांग में कई कार्यक्रमों के साथ की, जिनमें युवा सशक्तीकरण, उद्यमिता और शहरी बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और अन्य के साथ सीतारमण ने प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के तहत उत्तर पूर्व बैठक के एक संवाद सत्र की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने क्षेत्र के विभिन्न राज्यों के प्रशिक्षुओं, उद्योग जगत की हस्तियों और अधिकारियों के साथ बातचीत की। पीएमआईएस का उद्देश्य देश भर के युवाओं (विशेषकर दूरदराज के

क्षेत्रों के युवाओं) को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करके शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटना है। सत्र के दौरान, कई प्रशिक्षुओं ने योजना के माध्यम से व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास के अपने अनुभव साझा किए। अपने संबोधन में सीतारमण ने पीएमआईएस के पीछे के दृष्टिकोण को रेखांकित किया। उन्होंने कहा, इस योजना की परिकल्पना उन लोगों की सहायता के लिए की गई थी।

संक्षिप्त खबरें

धर्मांतरण के लिए नेपाल के रास्ते विदेशों से मिले 300 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने शुक्रवार को बताया कि जलालुद्दीन उर्फ छ्छांगुर बाबा को पिछले तीन वर्षों में लगभग 500 करोड़ रुपये की विदेशी फंडिंग मिली है। इसमें से 200 करोड़ रुपये की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि 300 करोड़ रुपये अवैध हवाला के जरिए नेपाल के रास्ते भेजे गए। एजेंसी के अनुसार, नेपाल के सीमावर्ती जिलों जैसे काठमांडू, नवलपरासी, रूपनदेही और बांके में 100 से ज्यादा बैंक खाते खोले गए थे। यह पैसा कथित तौर पर भारत में धर्मांतरण के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। नेपाल के एजेंटों ने 4–5: कमीशन लेकर, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के मधपुर निवासी छांगुर को यह धन हस्तांतरित करने में मदद की। कई मामलों में, नकद जमा मशीनों (सीडीएम) के माध्यम से धन जमा किया गया। यह धनराशि बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर जैसे भारतीय जिलों में लाई गई, जहां स्थानीय मुद्रा विनिमयकर्ताओं ने नेपाली मुद्रा को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया। कानून–व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि छांगुर बाबा का गिरोह लंबे समय से धर्मांतरण का काम कर रहा था। हनीट्रैप के जरिए दबाव बनाना, नाबालिगों को बहकाना और समाज में प्रभावशाली लोगों का इस्तेमाल करना – इन सबका इस्तेमाल धर्मांतरण के लिए किया जाता था।

नवी मुंबई में देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़

मुंबई, (एजेंसी)। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में पुलिस ने देह व्यापार रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया और नाबालिग लड़कियों समेत पांच महिलाओं को मुक्त कराया। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। नवी मुंबई पुलिस ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इस अवैध धंधे में शामिल लोग ग्राहकों को ऑनलाइन माध्यम से आकर्षित करते थे। ग्राहकों को नेरुल, वाशी और तुर्भे जैसे इलाकों में लॉज बुक करने के लिए कहा जाता था और आरोपी महिलाओं और लड़कियों को वहां भेजते थे। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आरोपी लोगों से प्रति घंटे 4,000 रुपये वसूलते थे। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए तुर्भे के एक होटल में आठ जुलाई को एक फर्जी ग्राहक भेजा। विज्ञप्ति के अनुसार, आरोपियों ने एक महिला को होटल भेजा जिसके बाद नवी मुंबई की मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ की एक टीम ने उस जगह पर छापा मारा और महिला को मुक्त कराया। विज्ञप्ति में कहा गया है कि आगे की जांच के परिणामस्वरूप नेरुल इलाके के एक फ्लैट से चार और महिलाओं और लड़कियों को मुक्त कराया गया तथा रैकेट के सरगना, एक बिचौलिए और एक ऑटोरिक्शा चालक सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस वर्तमान में तीन और आरोपियों की तलाश कर रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार व्यक्तियों को 14 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है।

यमुना को स्वच्छ बनाने पर मंथन, अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बड़ी बैठक

नई दिल्ली, (एजेंसी)।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ यमुना नदी के पुनरुद्धार पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल के साथ–साथ लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री भी बैठक में शामिल हुए। केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन और दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र भी गृह मंत्रालय और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के

साथ बैठक में मौजूद थे। चर्चा में यमुना नदी के पुनरुद्धार और पुनरुद्धार के लिए समन्वित प्रयासों और कार्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, जिसे दिल्ली के पर्यावरण और जन स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। इस सप्ताह की शुरुआत में, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी के जल बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, सीवरेज नेटवर्क को उन्नत करने, टैंकर सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ाने और अत्यधिक प्रदूषित यमुना नदी के पुनरुद्धार के उद्देश्य से एक 45–सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि 9,000 करोड़ रुपये के बजट वाली इस व्यापक योजना को अगले साल तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान का उद्देश्य राजधानी को स्वच्छ जल और प्रदूषण मुक्त यमुना उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री गुप्ता स्वयं नदी के पुनरुद्धार के प्रयासों का नेतृत्व कर रहे हैं, और उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना और लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा भी इस पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं।

मुझे देश की विदेश नीति के बारे में पूछने का अधिकार नहीं : भगवंत मान

बिहार, (एजेंसी)। प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही में संपन्न पांच देशों की यात्रा पर विदेश मंत्रालय द्वारा उनके बयान की निंदा किए जाने पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि क्या मुझे देश की विदेश नीति और उन्होंने वहां क्या किया, इसके बारे में पूछने का अधिकार नहीं है? भगवंत मान ने आगे कहा कि वह (प्रधानमंत्री) जहां भी जाते हैं, अडानी का कारोबार वहीं क्यों शुरू हो जाता है? मैं भविष्य में भी पूछता रहूंगा। देश में 140 करोड़ लोग हैं, उन्हें उनसे बातचीत करनी चाहिए और उनकी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। भगवंत मान ने निशाना साधते हुए आगे कहा कि वह कहते हैं कि वह यूक्रेन युद्ध (यूक्रेन–रूस) रोक देंगे, लेकिन वह पंजाब और हरियाणा के बीच पानी के

मुद्दे को भी हल नहीं कर सकते। इससे पहले विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि मान की टिप्पणी गैर–जिम्मेदाराना और अफसोसजनक थी। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि हमने एक उच्च सरकारी अधिकारी द्वारा वैश्विक दक्षिण के मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों के बारे में की गई कुछ टिप्पणियाँ देखी हैं। ये टिप्पणियाँ गैर–जिम्मेदाराना और खेदजनक हैं और सरकारी अधिकारी को शोभा नहीं देतीं। भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करती हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए मान ने कहा कि प्रधानमंत्री ऐसे देशों का दौरा कर रहे हैं जहाँ की आबादी 10,000 है। मान ने कहा कहा था कि प्रधानमंत्री कहीं गए हैं। मुझे लगता है कि वह घाना है। वह वापस आएँगे और उनका स्वागत है। भगवान ही जाने वह किन देशों में जाते रहते हैं, श्मैग्नेशियाश, श्गैल्वेइसाश, श्टार्वेसियाश। वह 140 करोड़ की आबादी वाले देश में नहीं रहते। वह ऐसे देशों में जा रहे हैं जहाँ की आबादी 10,000 है और उन्हें वहाँ श्सर्वोच्च पुरस्कारश मिल रहे हैं। यहाँ, 10,000 लोग एक जेसीबी देखने के लिए इकट्ठा होते हैं.।

प्रधानमंती और आरएसएस कार्टून मामले में सुप्रीम कोर्ट मे होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के आपत्तिजनक कार्टूनों के लिए इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालवीय की अग्रिम जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर द्वारा मामले की शीघ्र सुनवाई का अनुरोध करने के बाद मामले की सुनवाई 14 जुलाई के लिए स्थगित कर दी। हाथ से नहीं छूटा पौआ उन्होंने कहा, यह एक कार्टून के बारे में है जो मैंने 2021 में कोविड के दौरान बनाया था। यह अपराध बीएनएस के तहत आता है और इसके लिए अधिकतम तीन साल की सजा है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 3 जुलाई को उनकी

अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि मालवीय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया है और उन्हें विवादित व्यंग्यचित्र बनाते समय अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था। उनकी याचिका में स्पष्ट किया गया है कि उन्होंने मूल कार्टून कोविड–19 महामारी के चरम के दौरान प्रकाशित किया था, जब सोशल मीडिया पर टीकों की सुरक्षा और प्रभावकारिता से संबंधित गलत सूचना और भय व्याप्त था। उन्होंने कहा कि उनका कार्टून एक व्यंग्यात्मक व्यंग्य है, जो एक सार्वजनिक व्यक्ति द्वारा की गई टिप्पणियों पर सामाजिक टिप्पणी प्रस्तुत करता है कि कुछ टीके प्रभावी और ष्पानी की तरह सुरक्षितष हैं, भले ही उनकी प्रभावकारिता कठोर नैदानिक घ्परीक्षणों के माध्यम से अभी तक परखी नहीं गई है। यात्रियों के लिए राहत उन्होंने आगे दावा किया कि यह व्यंग्यचित्र कलाकार की कल्पना है जिसमें एक आम आदमी को एक जनप्रतिनिधि द्वारा टीका लगाया जा रहा है और यह चार वर्षों से अधिक समय से सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसमें कहा गया है कि एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता ने 1 मई, 2025 को कार्टून पोस्ट किया था, जिसमें कहा गया था कि ष्जाति जनगणना केवल वक्फ और पहलगाम जैसे मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का एक साधन है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मालवीय ने यह दिखाने के लिए वह पोस्ट साझा की कि उनके कार्टून सार्वजनिक उपयोग और अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध हैं,।

प्रधानमंत्री की घर वापसी के साथ भागवत ने दिलाई '75 साल' की याद : कांग्रेस

नई दिल्ली, (एजेंसी)। कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघचालक मोहन भागवत की 75 साल की उम्र में पद छोड़ने की कथित टिप्पणी को लेकर शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के लिए यह किस तरह की घर वापसी है कि विदेश से लौटने पर सरसंघचालक ने उन्हें याद दिलाया कि वह इस साल 75 साल के हो जाएंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री भी सरसंघचालक से कह सकते हैं कि वह भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। गत बुधवार को नागपुर में एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस प्रमुख भागवत ने एक कार्यक्रम में 75 साल की उम्र के बाद सेवानिवृत्त होने संबंधी टिप्पणी की थी। भागवत ने संघ विचारक मोरोपंत पिंगले की टिप्पणी का उल्लेख किया था कि जब 75 साल की उम्र पूरी होने पर शॉल आपके ऊपर डाला जाता है, तो इसका मतलब है कि आप एक निश्चित उम्र तक पहुंच गए हैं, अब आपको

अलग हट जाना चाहिए और दूसरों को काम करने देना चाहिए। रमेश ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, बेचारे अवार्ड–जीवी प्रधानमंत्री ! कैसी घर वापसी है यह ? लौटते ही सरसंघचालक ने याद दिला दिया कि 17 सितंबर 2025 को वह 75 साल के हो जाएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री भी सरसंघचालक से कह सकते हैं कि वह भी तो 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे! उन्होंने कटाक्ष किया, एक तीर, दो निशाने।

25,000 एकड़ जमीन अतिक्रमण मुक्त कराई : हिमंत

असम, (एजेंसी)। अतिक्रमण रोधी अभियान जारी रहने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा कि पिछले चार वर्षों में राज्य भर में 25,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। हालांकि, कांग्रेस ने अतिक्रमण रोधी अभियान की आलोचना की और वादा किया कि यदि विपक्षी

पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो भारतीय जनता पार्टी शासन के दौरान भूमि से बेदखल किए गए सभी भारतीय नागरिकों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। एक अन्य विपक्षी दल ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने धुबरी जिले में इस संबंध में विरोध प्रदर्शन किया। दो दिन पहले यहां बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा अतिक्रमण रोधी अभियान हिंसक हो गया था और पुलिस ने कथित अतिक्रमणकारियों को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया था। यहां कैबिनेट बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा, अभी तक असम सरकार ने पिछले चार वर्षों में हजारों बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया है। मेरे विचार से यह 25,000 एकड़ से कम जमीन नहीं है। यह बहुत अधिक है। शर्मा ने कहा कि वह अगले सप्ताह एक और प्रेस वार्ता करेंगे और मई 2021 में मुख्यमंत्री बनने के बाद से अतिक्रमण रोधी अभियान से संबंधित सभी आंकड़े प्रस्तुत करेंगे। कांग्रेस सांसद रकीबुल हुसैन ने कहा कि यदि राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो वह भाजपा सरकार के तहत चलाए गए अभियानों में बेदखल किए गए सभी भारतीय नागरिकों को मुआवजा देगी।

ईडी ने हरियाणा में सात जगहों पर छापे मारे

नई दिल्ली । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को फरवरी, 2025 में अमेरिका से निर्वासित अवैध प्रवासियों से संबंधित श्गधा रूट मामलेश के संबंध में हरियाणा में सात स्थानों पर तलाशी ली। जालंधर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हरियाणा के मनसा, कुरुक्षेत्र और करनाल में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि ये तलाशी 9 जुलाई को अमृतसर, संगरूर, पटियाला, मोगा, अंबाला, कुरुक्षेत्र और करनाल सहित 11 स्थानों पर किए गए पिछले तलाशी अभियान में एकत्रित विश्वसनीय इनपुट पर आधारित है, जिसमें कथित रूप से अवैध आव्रजन नेटवर्क में शामिल यात्रा और वीजा एजेंटों को निशाना बनाया गया था। प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि दूसरे चरण के व्यक्तियों और मानव तस्करों का उपयोग डोनकर्स (मानव तस्करी के माध्यम) के साथ मिलकर भारत के बाहर अवैध मार्ग संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। धन शोधन निवारण (पीएमएलए) जांच पंजाब और हरियाणा में राज्य पुलिस अधिकारियों द्वारा ट्रैवल एजेंटों और बिचौलियों के खिलाफ दर्ज 17 प्रथम सूचना रिपोर्टों (एफआईआर) के आधार पर शुरू की गई थी, जिन पर अमेरिका में प्रवास करने के लिए उत्सुक व्यक्तियों को धोखा देने का आरोप था। घटनाक्रम से अवगत प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने बताया कि, ये एजेंट कथित तौर पर लोगों को कानूनी यात्रा व्यवस्था का वादा करके फुसलाते थे, लेकिन इसके बजाय उन्हें खतरनाक, अवैध मार्गों से ले जाते थे, जिन्हें डोंकी रूट के नाम से जाना जाता है – यह शब्द अनधिकृत, बहु–देशीय भूमि पारगमन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो अक्सर खतरों से भरा होता है। गिरफ्तार ईडी के निष्कर्षों के अनुसार, एजेंटों ने कानूनी प्रवास के नाम पर प्रति व्यक्ति 45 से 50 लाख रुपये तक की अत्यधिक रकम वसूली।हालांकि, एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि पीड़ितों को अक्सर संगठित अपराध नेटवर्क और तथाकथित डॉन्कर्स (तस्करी में मदद करने वाले) की संलिप्तता से जंगलों और खतरनाक इलाकों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पार तस्करी कर लाया जाता था। अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ताओं ने यह भी बताया कि जब पीड़ित लोग यात्रा पर थे, तो एजेंटों और उनके सहयोगियों ने उनके प्रियजनों की सुरक्षा के प्रति भय और खतरे की भावना पैदा करके उनके परिवारों को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए मजबूर किया।

संपादकीय

जनसंख्या वृद्धि का अंत

विभिन्न धर्मग्रंथों में मानव की उत्पत्ति को लेकर भिन्न–भिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं। जब मनुष्य का इस धरा पर आगमन हुआ, तब उसके पास प्रकृति द्वारा प्रदत्त अनेक संसाधनों की भरमार थी। किंतु जैसे–जैसे जनसंख्या में वृद्धि हुई और विकास को मापने के आर्थिक मानक स्थापित हुए, जनसंख्या स्वयं एक गंभीर समस्या और चुनौती के रूप में उभरने लगी। जनसंख्या केवल धरती पर जीवित मानवों की संख्या की गणना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक अध्ययन इसके विभिन्न पहलुओं की गुणात्मक समझ प्रदान करता है। जनसंख्या के इस वैज्ञानिक अध्ययन को जनांकिकी (डैमोग्राफी) कहा जाता है, जो पिछले कुछ दशकों में वैश्विक स्तर पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है। जनांकिकी वह शास्त्र है जो जनसंख्या के आकार, संरचना, वितरण तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। जहां जनसंख्या का आकार मात्रात्मक विश्लेषण की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है, वहीं इसकी संरचना गुणात्मक विश्लेषण की संभावना को प्रकट करती है। जनसंख्या में परिवर्तन– जो वृद्धि या कमी का द्योतक होता है– मुख्यतरू जन्म, मृत्यु और प्रवास जैसे घटकों पर निर्भर करता है। जनसंख्या एक ओर जैविक तत्वों जैसे जन्म और मृत्यु से प्रभावित होती है, तो दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक कारक भी इसकी दिशा और स्वरूप को निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। पिछली दो सदियों में जनसंख्या वृद्धि में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। पृथ्वी की जनसंख्या को एक अरब तक पहुंचने में मानव इतिहास का अधिकांश समय लग गया। ।सेव त्मंक – म्कपजवतरू ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व करें, लेकिन सबसे बुरे हालात के लिए तैयार रहें चूंकि प्रारंभिक काल में जनसंख्या वृद्धि की दर बहुत धीमी थी, इसलिए विश्व की जनसंख्या वर्ष 1804 में जाकर पहली बार एक अरब के आंकड़े तक पहुंची। जनांकिकी की दृष्टि से इसे जनसंख्या वृद्धि की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है, जहां जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होती हैं, जिससे जनसंख्या की वृद्धि धीमी रहती है। वर्ष 1804 के बाद विश्व की जनसंख्या को एक अरब से दो अरब तक पहुंचने में 123 वर्ष लगे, और यह आंकड़ा वर्ष 1927 में प्राप्त हुआ। इसके बाद वृद्धि की गति तेज हो गई और मात्र 33 वर्षों में, वर्ष 1960 तक, जनसंख्या दो अरब से बढकर तीन अरब हो गई। इस बढ़ती रफ्तार का स्पष्ट उदाहरण वर्ष 2011 में देखा गया, जब वैश्विक जनसंख्या केवल 12.5 वर्षों में 6 अरब से बढकर 7 अरब तक पहुंच गई। इसके बाद, 7 अरब से 8 अरब तक पहुंचने में मात्र 11 वर्ष लगे। केवल 23 वर्षों में 2 अरब की वृद्धि जनसंख्या विस्फोट की स्थिति को दर्शाती है। इस काल खंड में अकाल, भुखमरी, बीमारियों पर अंकुश लग जाने से मृत्यु दर कम हुई। वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी से शिशु मृत्यु दर पर लगाम व जीवन प्रत्याशा दर में वैश्विक वृद्धि से भी जनसंख्या वृद्धि की दूसरी अवस्था से गुजरना पड़ा। वर्तमान समय में जनसंख्या वृद्धि की तीसरी और चौथी अवस्था को लेकर वैश्विक स्तर पर गंभीर चर्चा हो रही है। भले ही आज विश्व की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, लेकिन इसकी वृद्धि दर में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। जनसंख्या घटने के संकेत स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। मानव संसाधनों के ह्रास से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पडना स्वाभाविक है। जनसंख्या नीति को संतुलन और स्थायित्व की जरूरत है।

बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण संबंधी चिंताएं

अशोक

जरूरी नहीं जो कानूनी तौर पर हो, वह हमेशा उचित हो। मतदाता सूचियों का 'शोधन' एक सराहनीय उद्देश्य, एक जायज मांग और कठिन जिम्मेदारी है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सुकुमार सेन ने मतदाता सूची (ईआर) की गुणवत्ता पर अपनी पूरी तसल्ली होने बाद ही 1951 में प्रथम चुनाव करवाने से पहले, 18 महीने तक काफी दबाव झेला था। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी, जब इस साल की शुरुआत में, मतदाता सूची में कथित हेराफेरी और विसंगतियों की शिकायतों पर प्रतिक्रिया देते हुए 90 दिनों के अंदर सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन देश को दिया था। लेकिन इस दिशा में उठाए गए एक कदम ने चुनाव आयोग को विवाद के घेरे में ला दिया, जो कि पिछले कुछ समय से इस संस्थान को घेरने वाले कई विवादों में एक है। हालांकि इस मामले में अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। समय–समय पर चुनाव करवाने वाले काम के विपरीत, मतदाता सूची तैयार करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसमें जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 (2) और मतदाता पंजीकरण नियमों के नियम 25 के अनुसार प्रत्येक चुनाव से पहले संशोधन किया जाना शामिल है। इस हिसाब से, 2024 में हुए लोकसभा चुनावों से पहले एक राष्ट्रव्यापी संशोधन कार्य किया जाना बनता था। इस साल 24 जून को चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन करने का आदेश दिया, जबकि वहां होने वाले विधानसभा चुनाव में चंद महीने बाकी हैं। ऊपरी तौर से, इसका मंतव्य यह सुनिश्चित करना है कि 'मतदाता सूची में सभी पात्र नागरिक जुड़ें', 'कोई अयोग्य मतदाता न हो' और 'सूची में मतदाताओं को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता हो।' इस आदेश में गहन संशोधन हेतु विस्तृत प्रक्रिया की रूपरेखा दी गई, लेकिन इसने मतदाता सूची में 2003 से पहले और इसके बाद जुड़े मतदाताओं के बीच एक विवादास्पद अंतर खड़ा कर दिया, उस साल बिहार में आखिरी मर्तबा एसआईआर कार्य हुआ था। इस आदेश में 2003 के बाद जुड़े मतदाताओं को अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए, आयोग द्वारा तय दस्तावेज प्रस्तुत करके अपने दावों को सिद्ध करना अनिवार्य था। भले ही मतदाता के रूप में उनका नाम शामिल करते वक्त, 'जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23 के अनुरूप मतदाता संशोधन अधिकारी उनकी पात्रता की शर्तों की सत्यापना, अपनी तसल्ली होने तक, पहले ही कर चुका हो।' तर्क दिया गया, यह कार्य ईसीआईएनईटी पर शोधित सूची को प्रकाशित करने योग्य बनाएगा। यह घोषणा करने का वक्त और इसे अचानक किए जाने से हो–हल्ला मच गया, खासकर इसलिए कि यह प्रक्रिया उन अन्य राज्यों में नहीं करवाई गई जहां 'शुद्धीकरण' किया जाना इतना ही महत्वपूर्ण था और चुनाव भी तुरंत नहीं होने वाले थे। संदेह की वजह यह समझने में मुश्किल होना रही कि चुनाव आयोग किस चीज को आधार बनाकर 2003 तक पंजीकृत हुए लोगों की साक्ष्य–साख का अधिक मोल डाल रहा है। जबकि चुनाव आयोग खुद कहता है कि प्रवासन, मृत्यु, रोजगार आदि की संभावना दोनों श्रेणी के मतदाताओं पर लागू होती है। तो समझना मुश्किल है कि 2003 से पहले वाली और बाद वाली में अपनाई प्रक्रिया के बीच फर्क क्यों रखा जा रहा है? खासकर जब संक्षिप्त संशोधन या विशेष गहन संशोधन या चालू पंजीकरण के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एक जैसी है, जिसमें दस्तावेज जमा करवाए जाते हैं और बूथ स्तर का अधिकारी उनकी भौतिक सत्यापना करता है। 24 जून की प्रारंभिक अधिसूचना के अनुसार यह आशंका व्यक्त की गई कि 2003 के बाद पंजीकृत मतदाता यदि कोई संतोषजनक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहते हैं तो उनका नाम मसौदा मतदाता सूची से स्वतरू हट जाएगा। चुनाव आयोग के लिए अच्छा रहता यदि आदेश के साथ–साथ एक प्रेस नोट भी जारी करता, यह समझाने के लिए कि 24 जून के आदेश के पैरा 13 से जो अर्थ निकाले जा रहे हैं, वह वैसा नहीं है, जब उसमें कहा गया : 'मसौदा सूची में उन सभी मतदाताओं के नाम शामिल होंगे जो 25 जुलाई, 2025 से पहले–पहले विधिवत भरा हुआ पंजीकरण फॉर्म जमा करवा देंगे। चूंकि यह एक गहन संशोधन है, इसलिए यदि 25 जुलाई, 2025 से पहले पंजीकरण फॉर्म जमा नहीं करवाया जाता, तब मतदाता का नाम मसौदा सूची में शामिल नहीं किया जा सकेगा।' चुनाव आयोग को तुरंत स्पष्ट करना चाहिए था कि 'विधिवत भरे गए फॉर्म' से यहां आशय 'केवल वही फॉर्म जिनके साथ अपेक्षित दस्तावेज संलग्न हों' नहीं है व बूथ स्तरीय अधिकारी ऐसे पंजीकरण फार्म मसौदा सूची में शामिल न किए जाने की 'अनुशंसा' नहीं करेगा और नतीजन उनका नाम मसौदा मतदाता सूची से बाहर रह जाएगा। ऐसे स्पष्टीकरण से, मसौदा सूची से वोटर्स के नाम हट जाने बारे बनी गलतफहमी दूर होने में मदद मिलती। चूंकि तय किए दस्तावेज पेश करने की करोड़ों लोगों की क्षमता पर संदेह स्वाभाविक है, खासकर तब, जब चुनाव आयोग की स्वीकारोक्ति मुताबिक, यह काम पहले करना चाहिए था। इसका अहसास होने पर आयोग ने 30 जून को स्पष्टीकरण दिया : 'कोई भी व्यक्ति जिसका नाम 2003 की बिहार मतदाता सूची में नहीं है, वह अभी भी अपने माता या पिता के लिए कोई अन्य दस्तावेज प्रदान करने के बजाय 2003 की मतदाता सूची में दर्ज जानकारी का संदर्भ उपयोग कर सकता है३ इसके लिए, 2003 वाली मतदाता सूची वाला प्रासंगिक विवरण पर्याप्त होगा'। यह किए जाने से उन लोगों का बोझ हल्का हो गया होगा, जिनके लिए इससे पूर्व उक्त दस्तावेज पेश करना जरूरी था व उन्हें पाना कठिन हो सकता था। वास्तविक मतदाताओं द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने में संभावित व्यावहारिक कठिनाइयों के अलावा, जिस बात ने विवाद को और हवा दी, वह है चुनाव आयोग द्वारा जन्मतिथि के आधार पर अंतर करना जैसे 1 जुलाई, 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए अपने जन्म का दस्तावेजी सबूत देना अनिवार्य है, और 1 जुलाई, 1987 से 2 दिसंबर, 2004 के बीच पैदा हुए लोगों को 'अपना और पिता या माता में किसी एक का' कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है और 2 दिसंबर, 2004 के बाद जन्मे लोगों को 'अपना और पिता और माता, तीनों का' दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए जन्मतिथि औरध्या जन्म स्थान सिद्ध करना है। चुनाव आयोग का तर्क है कि यह अंतर विशेष गहन संशोधन की वजह से है, क्योंकि यह प्रावधान उस 'अनुच्छेद 326 को सख्ती से लागू करता है' जो 'भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक' को मताधिकार प्रदान करता है।

एक भारतीय आत्मा' को अभिनव आदरांजलि

विजयदत्त

वे समाज और राष्ट्र सच्चे अर्थों में समुन्नत होते हैं जो अपनी संस्कृति और परंपरा को सगर्व स्वीकारते हैं, और उनका अनुपालन करते हैं। ऐसे समाज अपने महनीय और कृती व्यक्तियों और उनके कृतित्व का स्मरण करते हैं, और उनके स्मारक भी रचते हैं। भारत से विदेश यात्रा पर जाने वाले लोग बहुधा अपने अनुभव सुनाते हुए उल्लेख करते हैं कि किन देशों और स्थानों पर उनके महान साहित्यकारों, कलाकारों, वैज्ञानिकों के सम्मान और स्मृति को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए किस प्रकार स्मृति चिह्नों को सहेजा गया है। भारत में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। भारत के सुदीर्घ और समृध्द्ध सांस्कृतिक इतिहास में अनेक विभूतियां हैं। इनमें मूर्धन्य साहित्यकार, शिरोमणि कलाकार, उद्भट विद्वान शिक्षाविद्, वैज्ञानिक सम्मिलित हैं। राष्ट्र की सीमाओं से परे विश्व फलक पर उनकी सर्जना को रेखांकित किया गया है। परंतु उन विभूतियों से संबंधित स्थलों के प्रति प्रायः उपेक्षा और उदासीनता का भाव ही हमारा स्वभाव है। यह जरूर है कि कुछ विभूतियों के नाम पर संस्थान स्थापित हुए हैं। ऐसे परिवेश और सामाजिक पर्यावरण में बीते दिनों भारत के हृदय मध्यप्रदेश में घटित ऐतिहासिक परिघटना ने इस जड़ता को तोड़ा है। मध्यप्रदेश के नर्मदापुरमद्द (होशंगाबाद) जिले के बाबई गांव में जन्मे दादा माखनलाल चतुर्वेदी चिंतक, कवि, संपादक, स्वाधीनता आंदोलन के अग्रगण्य हस्ताक्षर रहे हैं। प्रभा और कर्मवीर के संपादक के रूप में उन्होंने राष्ट्र की वाणी को मुखरित किया। जब योद्धा पत्रकार गणेश शंकर विद्यार्थी कारावासी हुए, तब माखनलाल जी ने 'प्रताप' के संपादन का दायित्व संभाला। कवि–लेखक की भूमिका में मानवीय संवेदना और सरोकारों के साथ–साथ स्वाधीनता की चेतना को स्वर दिया। वे गिरफ्तारी देने वाले मध्य प्रांत के पहले सत्याग्रही थे। ऐतिहासिक झण्डा सत्याग्रह के नायक थे। बिलासपुर जेल में 18 फरवरी, 1922 को जिस 'पुष्प की अभिलाषा' की उन्होंने रचना की, वह समूचे देश के लिए आजादी का तराना बन गई थी। ऐसी राष्ट्रीय विभूति की जन्मभूमि बाबई उपेक्षित थी। सनद्द 1988–89 दादा माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म शताब्दी वर्ष था। इस प्रसंग में माधवराव सप्रे स्मृति समाचारपत्र संग्रहालय, भोपाल ने बाबई में माखनलाल चतुर्वेदी जन्म शताब्दी समारोह का आयोजन किया। साहित्य और पत्रकारिता के शीर्षजनों ने इस मंच से दादा की जन्मस्थली बाबई का नामकरण 'माखननगर' करने की अपील की। 4 अप्रैल, 1988 को माखनलाल जी के सौवें जन्मदिन पर मध्यप्रदेश विधानसभा ने सर्वसम्मति से तदाशय का संकल्प पारित किया। उस समय सदन के नेता मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह, नेता प्रतिपक्ष कैलाश जोशी और विधानसभा अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद शुक्ल थे। विधानसभा में इन तीनों संवैधानिक हस्तियों की वाणी में मानो मध्यप्रदेश के कोटिशः कण्ठों का कृतज्ञ स्वर मुखरित हुआ था। तथापि प्रक्रिया की भूल–भुलैया में इस संकल्प का साकार होना उलझा रहा। आखिरकार दादा माखनलाल चतुर्वेदी की 134वीं जयंती आते–आते नामकरण की जन–अभिलाषा पूरी होने की घड़ी आ गई। मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, के निरंतर प्रयासों के कारण संकल्प साकार हो सका। एक विशाल जनसभा में हजारों नागरिकों की उपस्थिति में 'बाबई' से 'माखननगर' नामकरण का समारोह मनाया गया। बाबई में जितने भी शासकीय और अर्द्धशासकीय कार्यालय स्थापित थे, उन सभी के नामपट पर 'माखननगर' अंकित किया गया। वैसे बाबई के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान कई साल पहले से अपने नामपट में माखननगर जोड़ चुके थे। नागरिक अपने पत्र–व्यवहार में और पत्रकार अपने समाचारों के साथ माखननगर नाम का प्रयोग कर रहे थे।

.... विविध ....

इससे कैंसर से लेकर इन बीमारियों तक का खतरा

जब हम किसी मॉल या बड़ी दुकान से सामान खरीदते है तो हमें पेपर रसीद मिलती है। अधिकतर लोग इसे बिना सोचे–समझे हाथ में पकड़ लेते हैं या पर्स में रख लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये छोटी–सी रसीद भी आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकती है? इसका कारण है रसीद में इस्तेमाल होने वाला थर्मल पेपर, जिसमें खतरनाक रसायन और कभी–कभी BPA पाए जाते हैं।

थर्मल पेपर क्या होता है?

थर्मल पेपर एक खास प्रकार का कागज होता है जिस पर एक रासायनिक कोटिंग की जाती है। जब यह पेपर थर्मल प्रिंटर से गुजरता है, तो प्रिंटर की गर्मी उस कोटिंग को सक्रिय कर देती है और वही कोटिंग टेक्स्ट या इमेज में बदल जाती है। यही प्रक्रिया बिना इंक के प्रिंटिंग को संभव बनाती है, लेकिन इसी कोटिंग में मौजूद BPA या BPA हमारे लिए खतरनाक हो सकते हैं।

कैसे नुकसान करता है?

BPA एक एंडोक्राइन डिसरप्टर है। यह शरीर के हार्मोन सिस्टम में दखल देता है, विशेष रूप से एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन के स्तर को प्रभावित करता है। इसका असर पुरुषों और महिलाओं दोनों के शरीर पर पड़ सकता है।

स्वास्थ्य पर क्या–क्या असर पड़ सकते हैं?

एसजीटी यूनिवर्सिटी, गुरुग्राम के फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉ. भूपेश कुमार शर्मा बताते हैं कि

ठच। के संपर्क में आने से हार्मोनल असंतुलन हो सकता है

महिलाओं में PCOS, बांझपन, और स्तन कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं

पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ सकता है

थायरॉइड की कार्यप्रणाली भी प्रभावित हो सकती है

बच्चों में ADHD (अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर) और अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याएं हो सकती हैं

किन लोगों को ज्यादा खतरा?

गर्भवती महिलाएं– गर्भ में पल रहे बच्चे पर असर

छोटे बच्चे– मानसिक और शारीरिक विकास में रुकावट

किशोररू हार्मोनल असंतुलन की ज्यादा संभावना

इन रसीदों से कैसे बचें?

स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए इन बातों का ध्यान रखेंरू

रसीद को सीधे हाथों से न छुएं, खासकर जब हाथ गीले हों

अगर जरूरी न हो, तो डिजिटल रसीद ही लें

रसीद को खाने–पीने की चीजों से दूर रखें

बिल को बच्चों और गर्भवती महिलाओं से दूर रखें

रसीद छूने के बाद हाथ जरूर धोएं

थर्मल रसीद को रीसायकल न करें, इससे केमिकल अन्य उत्पादों में मिल सकते हैं

अगर आपको बार–बार रसीदों से काम पड़ता है, जैसे कैशियर या स्टोर कर्मचारी के रूप में, तो ग्लव्स पहनना और सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। रसीद को हम अक्सर मामूली समझ लेते हैं, लेकिन उसमें छिपे केमिकल्स हमारी सेहत को गंभीर नुकसान पहुँचा सकते हैं।

स्किन डैमेज के पीछे छुपी 5 आम गलतियां, समय रहते सुधरें

दमकती यानी ग्लोइंग स्किन केवल आपकी सुंदरता का प्रतीक नहीं होती, बल्कि यह आपके अच्छे स्वास्थ्य की भी निशानी होती है। हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा साफ–सुथरी, मुलायम और चमकदार दिखे। लेकिन बढ़ता प्रदूषण, गलत लाइफस्टाइल और तनाव आपकी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज के समय में लोग महंगे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन कई बार इसका कोई फायदा नहीं होता। अगर आपकी त्वचा में सुधार नहीं हो रहा तो शायद आपकी रोजमर्रा की कुछ आदतें इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। आइए जानते हैं किन गलत आदतों से आपकी त्वचा खराब हो सकती है।

पानी की कमी से त्वचा सूखी और बेजान हो सकती है

त्वचा की सबसे पहली जरूरत है पानी। जब हमारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाता है तो त्वचा ड्राई और झुर्रियों वाली लगने लगती है। इसलिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना जरूरी है। इससे त्वचा अंदर से हाइड्रेट रहती है और चमकदार दिखती है।

खराब डाइट से त्वचा को नुकसान

आजकल ज्यादातर लोग स्वाद और टेस्ट पर ध्यान देते हैं, लेकिन सही पोषण पर कम ध्यान देते हैं। स्किन के लिए फल, सब्जियां, नट्स और सीड्स का सेवन बहुत जरूरी है। इनमें विटामिन ब और एंटीऑक्सिडेंट होते हैं जो त्वचा के सेल्स को रिपेयर करते हैं और स्किन को जवान बनाते हैं।

नींद पूरी न होना बन सकता है बड़ी समस्या

अक्सर लोग अपने बिजी शेड्यूल के कारण पूरी नींद नहीं ले पाते। नींद पूरी न होने पर त्वचा के सेल्स रिपेयर नहीं हो पाते, जिससे त्वचा थकी–थकी और बेजान दिखती है। रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेना बेहद जरूरी है, जिससे त्वचा में ग्लो आता है और आपकी ताजगी बनी रहती है।

सनस्क्रीन का सही इस्तेमाल जरूरी

धूप में मौजूद न्ट किरणें त्वचा को काला, सूखा और झुर्रियों वाला बना सकती हैं। इसलिए घर से निकलने से कम से कम 20 मिनट पहले ैच्थ् 30 या उससे ऊपर वाला सनस्क्रीन लगाना चाहिए। यह आपकी त्वचा को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएगा और त्वचा को स्वस्थ रखेगा।

तनाव को कम करें, योग और ध्यान अपनाएं

तनाव का असर सीधे आपकी त्वचा पर दिखता है। ज्यादा तनाव होने पर चेहरे पर झुर्रियां और त्वचा की चमक कम हो जाती है। ध्यान, योग और हल्का व्यायाम तनाव को कम करते हैं और आपकी त्वचा को हेल्दी बनाए रखते हैं। रोजाना थोड़ी देर मेडिटेशन और योग करना आपकी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है।

लगातार देखभाल और सही आदतें बनाएं

ग्लोइंग स्किन पाने के लिए जादू की जरूरत नहीं है, बल्कि यह नियमित देखभाल, सही जीवनशैली और त्वचा की सही समझ से संभव है।आप अपनी त्वचा को जितना प्यार और ध्यान देंगे, वह उतनी ही ज्यादा चमकेगी। इसलिए त्वचा की देखभाल को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और सही आदतें बनाएं।

अगर आप अपनी त्वचा को हेल्दी और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं तो रोजाना खूब पानी पिएं, संतुलित आहार लें, पूरी नींद लें, सनस्क्रीन लगाएं और तनाव कम करने के लिए योग और ध्यान करें। इन सरल आदतों से आपकी त्वचा स्वस्थ और दमकती बनी रहेगी। याद रखें, त्वचा की सही देखभाल ही असली खूबसूरती की चाबी है।

इस मंदिर में साल में तीन बार रंग बदलता है शिवलिंग

पवित्र श्रावण मास की शुरुआत के साथ उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में पौराणिक तिलेश्वर महादेव मंदिर पर शिव भक्तों का सैलाब पहुंचने लगा है। जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूर काशी– प्रयाग के मध्य भदोही जिले के तिलंगा में स्थित तिलेश्वर महादेव मंदिर का अपना ऐतिहासिक व पौराणिक महामात्य है। बताया जाता है कि मंदिर में स्थापित अछ्वुत शिवलिंग साल में तीन बार रंग बदलता है।

प्रमुख ज्योतिषाचार्य एवं इतिहास विद पंडित आलोक शास्त्री ने बताया कि वैसे तो पूर्वांचल में ऐसे कई धार्मिक मंदिर व धरोहर हैं जिनका इतिहास पौराणिक होने के साथ ही लोगों के आस्था का केंद्र भी हैं। इन्हीं प्राचीन व पौराणिक मंदिरों व तीर्थ स्थलों में शुमार जिले के गोपीगंज क्षेत्र के तिलंगा में स्थित तिलेश्वर नाथ मंदिर में स्थापित छ्वुत शिवलिंग साल में तीन बार अपने स्वरूप बदलने के कारण प्राचीन काल से ही सनातनियों की आस्था का केंद्र बिंदु बना हुआ है। जहां साल भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। पवित्र श्रावण मास में तो तो इस मंदिर का माहात्म्य काफी बढ़ जाता है।

भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्त सैकड़ों किलोमीटर की पैदल कांवड़ यात्रा कर जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। गंगा के तट पर स्थित मंदिर का यह शिवलिंग अपने रहस्यमयी स्वरूप के लिए जाना जाता है। पांडवकालीन शिवलिंग वर्ष की तीन ऋतुओं में तीन बार अपना स्वरूप बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इस पर भक्तों की अपार श्रद्धा और विश्वास है। मान्यता है कि पांडवों ने इसे अपने अज्ञातवास के दौरान स्थापित किया था। मंदिर के पुजारी महादेव गोसाई ने शिवलिंग के रहस्य के बारे में बताया कि यह शिवलिंग सावन के महीने में चप्पड़ (ऊपरी परत) छोड़ता है, लेकिन वह आज तक किसी के हाथ नहीं लग सका है। उन्होंने बताया कि सच्चे मन से जो भी मुराद मांगी जाती है, वह अवश्य पूरी होती है।

12 जुलाई को अवकाश के बावजूद खुले रहेंगे नगर निगम कार्यालय

लखनऊ, (संवाददाता)। करदाताओं की सुविधा और समय पर कर भुगतान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लखनऊ नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए शनिवार, 12 जुलाई 2025 को सार्वजनिक अवकाश के बावजूद अपने सभी जोनल कार्यालय खुले रखने की घोषणा की है। इस विशेष व्यवस्था के तहत भवन स्वामी अपने गृहकर का भुगतान कर 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि यह छूट केवल उन्हीं करदाताओं को मिलेगी जो पहले अपना यूजर चार्ज एकमुश्त जमा करते हैं और उसके बाद गृहकर का भुगतान करते हैं। यह सुविधा 31 जुलाई 2025 तक के लिए सीमित है। इस छूट योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक नागरिकों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना है।नगर निगम द्वारा 12 जुलाई को सभी जोनल कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। यह विशेष प्रबंध उन नागरिकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जो सामान्य कार्यदिवसों में अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण कार्यालय जाकर कर भुगतान नहीं कर पाते।महापौर सुषमा खर्कवाल ने लखनऊवासियों से अपील करते हुए कहा कि नगर निगम की इस सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि समय पर कर भुगतान केवल करदाता को छूट का लाभ नहीं देता, बल्कि इससे नगर निगम को शहर में बेहतर बुनियादी सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।नगर निगम ने नागरिकों से यह भी आग्रह किया है कि वे इस अवसर को गंभीरता से लें और अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए लखनऊ को एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और विकसित शहर बनाने में सहयोग दें।

पुलिस बेबस, छह माह में 341 लूट लखनऊकमिश्नरेट पुलिस ने अखबार की खबर को बताया भ्रामक और निराधार

लखनऊ, (संवाददाता)। एक प्रमुख स्थानीय समाचार पत्र में 11 जुलाई को प्रकाशित एक खबर में यह दावा किया गया था कि जनवरी से जून 2025 के बीच लखनऊ में 341 लूट की घटनाएं हुई हैं। खबर में यह भी कहा गया कि पुलिस बेबस है और अपराधियों के सामने घुटने टेक चुकी है। इस खबर पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि उक्त दावा तथ्यहीन, भ्रामक और निराधार है, जिसका उद्देश्य केवल जनता के बीच भय और भ्रम फैलाना प्रतीत होता है।पुलिस की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि वर्ष 2025 में 1 जनवरी से अब तक लखनऊ कमिश्नरेट क्षेत्र में लूट और स्नैचिंग की केवल 107 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें मोबाइल, पर्स और चैन स्नैचिंग जैसे अपराध भी शामिल हैं। पुलिस ने न केवल इन घटनाओं का त्वरित संज्ञान लिया, बल्कि प्रभावी कार्रवाई करते हुए इन मामलों में कुल 162 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 14 शातिर अपराधियों को पुलिस मुठभेड़ों के दौरान पकड़ा गया है।मध्य, पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी पांचों जोन लखनऊ के सभी जोनों में पुलिस ने मुस्तैदी से काम करते हुए लूट की घटनाओं का निस्तारण किया है। मध्य जोन में कुल 24 घटनाएं दर्ज हुईं, वहीं पुलिस ने 29 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर ₹4,01,700 की लूटी गई संपत्ति बरामद की। पूर्वी जोन में 19 घटनाओं में 37 अभियुक्त पकड़े गए और ₹8,21,200 की संपत्ति बरामद की गई। उत्तरी जोन में 12 मामलों में 23 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से ₹6,44,720 की लूटी गई राशि वापस ली गई। दक्षिणी जोन में 28 लूट की घटनाएं दर्ज हुई और 38 अभियुक्तों को पकड़कर ₹4,24,370 की संपत्ति बरामद की गई। वहीं पश्चिमी जोन में 24 घटनाओं में 35 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई और ₹3,29,040 की संपत्ति पुलिस ने बरामद की।पुलिस ने बताया कि इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और धारा 107 बीएनएसएस के तहत सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनकी अवैध संपत्तियों की कुर्की हेतु न्यायालय में रिपोर्टें भेजी जा चुकी हैं। साथ ही अपराध से अर्जित धन की जब्ती की कार्रवाई भी तेजी से चल रही है। पुलिस का कहना है कि अपराध नियंत्रण के लिए निरंतर अभियान चलाए जा रहे हैं और अभियोजन स्तर पर प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को कड़ी सजा दिलाई जा रही है।लखनऊ कमिश्नरेट ने यह भी कहा है कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रही इस सक्रिय कार्रवाई के बावजूद जब कुछ मीडिया संस्थान भ्रामक आंकड़ों के आधार पर खबरें प्रकाशित करते हैं, तो इससे न केवल पुलिस बल का मनोबल गिरता है, बल्कि आम नागरिकों में भी बेवजह की घबराहट फैलती है। पुलिस ने मीडिया से अपील की है कि तथ्यपरक और प्रामाणिक जानकारी के आधार पर ही समाचार प्रकाशित किए जाएं।पुलिस कमिश्नरेट ने आश्वस्त किया है कि शहर में संगठित अपराध पर पूरी तरह नियंत्रण है और भविष्य में भी अपराध के विरुद्ध 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।

संक्षिप्त खबरें

मुजफ्फरनगर के दो होनहार युवाओं ने नीट 2025 में दिखाई देशभर में चमक

लखनऊ (संवाददाता)। मुजफ्फरनगर की धरती एक बार फिर गौरवान्वित हुई है, जब यहां के दो सामान्य परिवारों से आने वाले मोहम्मद सुहैल और मोहम्मद उज्जैर ने नीट 2025 जैसी प्रतिष्ठित और कठिन परीक्षा में उत्कृष्ट सफलता हासिल की। यह सफलता न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष और मेहनत की जीत है, बल्कि उन सभी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखते हैं।प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन दोनों मेधावी युवाओं की उपलब्धि को विशेष रूप से सराहा और उन्हें सम्मानित करने के निर्देश व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल को दिए। मंत्री अग्रवाल ने शुक्रवार को मोहम्मद सुहैल के आवास ईदगाह रोड और मोहम्मद उज्जैर के घर मदीना चौक, सरवट जाकर मिठाई खिलाई, पुष्प माला पहनाकर दोनों परिवारों के साथ सफलता का जश्न मनाया।मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इस अवसर पर कहा कि सुहैल और उज्जैर की सफलता कड़ी मेहनत, आत्मविश्वास और पारिवारिक सहयोग का प्रमाण है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ऐसे मेधावी युवाओं को हर संभव सहायता प्रदान करने को प्रतिबद्ध है और मेडिकल शिक्षा के लिए भी यदि आवश्यक हो तो पूरी मदद करेगी।मोहम्मद सुहैल, जो किदवई नगर स्थित दरोगा की कोठी के रहने वाले हैं, एक रिक्शा चालक इजरार के पुत्र हैं।

उत्तर प्रदेश में विमान रखरखाव और ओवरहॉल सुविधाओं के विकास हेतु नई नीति लागू

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में वायुयानों के रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहॉल (एमआरओ) सुविधाओं के समुचित विकास के लिए एक महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिया है। नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा प्रस्तुत नवीनतम दिशा–निर्देशों एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया को औपचारिक रूप से अनुमोदित कर दिया गया है, जो राज्य में पूंजी निवेश को आकर्षित करने, एविएशन उद्योग को संस्थागत आधार प्रदान करने तथा विमानन क्षेत्र को रोजगारपरक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ए.एस.पी. गोयल ने 30 जून 2025 को निदेशक नागरिक उड्डयन को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। यह निर्णय उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी एविएशन हब बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा है। वर्ष 2022 में जारी शासनादेश संख्या 50६2022 के तहत पहले ही पूंजी निवेश के लिए प्रोत्साहन एवं सुविधा प्रदान की गई थी, जिसमें निवेशकों के लिए भूमि आवंटन, बुनियादी ढांचे, सिंगल विंडो क्लियरेंस, बिजली–पानी जैसी आवश्यक सेवाओं में प्राथमिकता सुनिश्चित की गई है।राज्य सरकार ने आवेदन की अंतिम तिथि को अब 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दिया है, जिससे निवेशकों को अधिक समय मिलेगा। नवीनतम दिशा–निर्देशों के कार्यान्वयन से एमआरओ गतिविधियों की स्थापना जमीन पर प्रभावी रूप से संभव होगी। इसके तहत निवेशकों को समयबद्ध अनुमति प्रक्रिया और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

मिर्जापुर के गाँवों में खुलेगा ग्रामीण पर्यटन का नया द्वार, पहले चरण में आठ गांव होंगे विकसित

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी माने जाने वाले मिर्जापुर को अब ग्रामीण पर्यटन के रूप में एक नई पहचान मिलने जा रही है। अपनी आध्यात्मिक आभा और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विख्यात यह क्षेत्र अब पर्यटन विभाग की एक महत्वाकांक्षी योजना के माध्यम से देश–विदेश के पर्यटकों को गाँवों की ओर आकर्षित करने को तैयार है। योजना का उद्देश्य न सिर्फ ग्रामीण आर्थिकी को सशक्त करना है, बल्कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पटल पर स्थापित करना भी है।पर्यटन विभाग द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत मिर्जापुर, सोनभद्र और भदोही जिलों के चुनिंदा गाँवों को ग्रामीण और कृषि पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस योजना को पांच चरणों में लागू किया जाएगा, जिसके पहले चरण में आठ गाँवों का चयन किया गया है। इन गाँवों में स्थानीय जीवनशैली, संस्कृति, हस्तशिल्प और पारंपरिक आजीविका को पर्यटन के माध्यम से उभारा जाएगा।पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि "यह पहल केवल पर्यटन नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रयास है। हम गाँवों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, ताकि वहाँ के लोग अपनी परंपराओं और संसाधनों के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर सकें।"योजना के अनुसार, प्रत्येक गाँव में एक स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया जाएगा जिसे राज्य और जिला स्तरीय टीमों का सहयोग मिलेगा। इन टीमों में पर्यटन, संस्कृति और ग्रामीण विकास के विशेषज्ञ शामिल होंगे। इन गाँवों में कम से कम चार आधुनिक होमस्टे तैयार किए जाएंगे, जिनमें साफ–सुथरे कमरे, स्वच्छ शौचालय, इंटरनेट, डिजिटल पेमेंट, पीओएस मशीन और क्यूआर कोड जैसी सुविधाएं होंगी, ताकि आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।इन गाँवों में पारंपरिक हस्तशिल्प, जैसे जरी–जरदोजी कढ़ाई, मूनज घास से बने उत्पाद, लकड़ी के खिलौने और वव्क (वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट) से जुड़े उत्पादों को विशेष स्थान दिया जाएगा। गाँवों में इन उत्पादों के लिए विशेष दुकानें खोली जाएंगी और उन्हें डिजिटल भुगतान के अनुकूल बनाया जाएगा, जिससे शिल्पियों को सीधे लाभ मिलेगा।योजना में सोशल मीडिया की भूमिका भी अहम होगी। प्रत्येक गाँव के लिए अलग–अलग सोशल मीडिया अकाउंट बनाए जाएंगे जहां फोटो, वीडियो और रील्स के माध्यम से वहाँ की सांस्कृतिक विविधता, लोकगीत, लोकनृत्य, भोजन और पर्यावरणीय खूबसूरती को विश्वभर में प्रचारित किया जाएगा।इसके अतिरिक्त, प्रत्येक तिमाही में प्रशिक्षण शिविर, जागरूकता कार्यक्रम और पर्यटक सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, ताकि स्थानीय समुदाय की भागीदारी निरंतर बनी रहे और गाँव की पहचान एक पर्यटन केंद्र के रूप में मजबूत हो सके। राष्ट्रीय और स्थानीय टूर ऑपरेटरों के साथ साझेदारी कर इन गाँवों को टूरिज्म सर्किट में जोड़ा जाएगा।योजना की सफलता की कहानियाँ वृत्तचित्रों के रूप में तैयार कर हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रस्तुत की जाएंगी, जिससे यह मॉडल अन्य जिलों और राज्यों के लिए भी प्रेरणा बन सके। यह पहल मिर्जापुर के ग्रामीण क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे नगर निगम कार्यालय, गृहकर जमा करने वालों को मिलेगा 10प्रतिशत छूट का लाभ

लखनऊ, (संवाददाता)। करदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ नगर निगम ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शनिवार, 12 जुलाई 2025 को सार्वजनिक अवकाश होने के बावजूद नगर निगम के सभी जोनल कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि भवन स्वामी अपने गृहकर का भुगतान समय से कर सकें और 10 प्रतिशत की विशेष छूट का लाभ ले सकें।नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अशोक सिंह ने बताया कि यह छूट केवल उन करदाताओं को दी जाएगी जो पहले अपने यूजर चार्ज का एकमुश्त भुगतान करते हैं और उसके बाद गृहकर जमा करते हैं। यह विशेष सुविधा 31 जुलाई 2025 तक लागू रहेगी।12 जुलाई को सभी जोनल कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे और गृहकर संबंधी सभी कार्य यथावत संपन्न किए जाएंगे। यह निर्णय खासतौर पर उन नागरिकों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जो सप्ताह के अन्य दिनों में कार्यालयी व्यस्तता के कारण कर जमा नहीं कर पाते हैं।महापौर सुषमा खर्कवाल ने लखनऊवासियों से अपील की है कि वे नगर निगम की इस सुविधा का लाभ उठाएं और समय रहते यूजर चार्ज एवं गृहकर का भुगतान कर छूट प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि करदाताओं का यह योगदान न केवल उन्हें आर्थिक रूप से लाभान्वित करेगा, बल्कि शहर के विकास और नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने में भी सहायक सिद्ध होगा।नगर निगम प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे इस अभियान में भाग लेकर लखनऊ को एक स्वच्छ, सुव्यवस्थित और विकसित शहर बनाने की दिशा में सक्रिय भूमिका निभाएं।

स्कूल बंद कर योगी सरकार कर रही बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ : संजय सिंह

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के स्कूल बचाओ अभियान के तहत पार्टी के प्रदेश प्रभारी व राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने गुरुवार को लखनऊ के बीकेटी क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय सहपुरवा का दौरा किया। स्कूल बंद होने और उसके विलय से परेशान बच्चों व अभिभावकों से मुलाकात कर संजय सिंह ने उनके साथ करीब ढाई किलोमीटर तक पदयात्रा की, जहां इन बच्चों को अब पढ़ने के लिए भेजा गया है।पदयात्रा के दौरान संजय सिंह ने कहा कि छोटे–छोटे मासूम बच्चों को रोज ढाई किलोमीटर दूर स्कूल भेजना अत्याचार है। बच्चों के पास पहनने को चप्पल तक नहीं है, और रास्ते में व्यस्त सड़क, जंगल और बंदरों से खतरा बना रहता है। यह उनके जीवन से सीधा खिलवाड़ है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार कानून स्पष्ट कहता है कि एक किलोमीटर के दायरे में प्राथमिक विद्यालय होना चाहिए, लेकिन सरकार उस कानून को भी दरकिनार कर रही है।इस मौके पर एक स्थानीय महिला ने बताया कि जब उनके बच्चों को

स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए प्रयास किया गया, तो उन्हें मना कर दिया गया। जबकि दर्जनों बच्चे पढ़ने को तैयार थे। इस पर संजय सिंह ने कहा कि यह भेदभाव दलित, शोषित और पिछड़े वर्गों के बच्चों के साथ हो रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि वे इस गांव में आकर अपनी नीतियों के दुष्परिणाम स्वयं देखें।संजय सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में 27 हजार प्राथमिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, जो सीधे तौर पर गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी इस तानाशाही के खिलाफ संघर्ष करेगी और बंद स्कूलों को फिर से शुरू कराने के लिए जन आंदोलन तेज किया जाएगा।संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि बंद किए गए सभी प्राथमिक विद्यालयों को तत्काल पुनः चालू किया जाए, बच्चों को स्थानीय स्तर पर शिक्षा की सुविधा मिले और प्रदेश में नए स्कूल खोले जाएं, साथ ही शिक्षकों की भर्ती भी सुनिश्चित की जाए।उन्होंने सभी अभिभावकों और नागरिकों से आह्वान किया कि वे इस अभियान से जुड़ें

मुरादाबाद में समाज कल्याण विभाग की बड़ी कार्रवाई, अधीक्षिका निलंबित, डीएसडब्ल्यू पर जांच के आदेश

लखनऊ, (संवाददाता)। प्रदेश सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत मुरादाबाद में एक और सख्त कार्रवाई की गई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में रखरखाव के नाम पर जारी किए गए 10 लाख रुपये की अनियमितता के मामले में छात्रावास की अधीक्षिका सुश्री प्रवेश कुमारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश भी जारी कर दिए हैं।यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब 7 जुलाई को मुरादाबाद में मंत्री असीम अरुण एक छात्रावास कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान छात्रावास के छात्रों ने मंत्री के समक्ष कई गंभीर शिकायतें रखीं, जिनमें छात्रावास की दुर्दशा और फर्जी रखरखाव कार्यों का मुद्दा प्रमुख था।छात्रों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मंत्री ने तत्काल मेरठ मंडल की उपनिदेशक सुनीता यादव को जांच के लिए भेजा। 10 जुलाई को उपनिदेशक ने जब छात्रावास का निरीक्षण किया, तो शिकायतें सही पाई गईं। जांच में सामने आया कि मार्च 2025 में कागजों पर 14 सीसीटीवी कैमरे खरीदे और लगाए जाने की पुष्टि की गई थी, लेकिन असल में ये कैमरे 9 जुलाई को्ल्यानी जांच के ठीक एक दिन पहले लगाए गए थे। इसी प्रकार, 42 इंच का एक एलईडी टीवी भी मार्च में लगाया जाना दर्शाया गया था, जबकि वह वास्तव में 7 जुलाई को ही छात्रावास में लगाया गया।इतना ही नहीं, कमरों और खिड़कियों की पुताई, मुख्य गेट की मरम्मत और रंगाई–पुताई के कार्य भी फर्जी पाए गए। जांच अधिकारी को इन सभी कार्यों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी, लापरवाही और वित्तीय अनियमितताएं मिलीं।प्रदेश सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अधीक्षिका के निलंबन का निर्णय लिया है और पूरे प्रकरण की जांच का दायरा बढ़ा दिया है। मंत्री असीम अरुण ने स्पष्ट किया है कि समाज कल्याण विभाग में किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार छात्रों के कल्याण और अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और ऐसे मामलों में कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकारी धन का दुरुपयोग रोका जा सके और छात्रावासों की दशा में सुधार सुनिश्चित किया जा सके।

संक्षिप्त खबरें

विश्व युवा कौशल दिवस पर 15–16 जुलाई को भव्य कौशल मेला

लखनऊ, । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार "कौशल युक्त युवा, सशक्त भारत" के संकल्प को साकार करने के लिए आगामी 15 और 16 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के उपलक्ष्य में दो दिवसीय भव्य कौशल मेले का आयोजन करने जा रही है। यह आयोजन उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा किया जाएगा, जिसका संचालन व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल के निर्देशन में होगा।मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि यह मेला प्रदेश के युवाओं को उनके कौशल प्रदर्शन का मंच देने के साथ–साथ उन्हें उद्यमशीलता एवं रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने युवाओं से इस अवसर का लाभ उठाने और प्रदेश की औद्योगिक एवं नवाचार यात्रा में भागीदार बनने की अपील की।मिशन निदेशक पुलकित खरे ने जानकारी दी कि यह कौशल मेला पूर्णतः निःशुल्क रहेगा और इसमें 100 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे। इन स्टॉलों पर विभिन्न ट्रेडों से संबंधित प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार उत्पादों का प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाएगा। हैंडीक्राफ्ट्स, स्पोर्ट्स आइटम्स, चिकनकारी, टेक्सटाइल, हेल्थकेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कारपेट और घरेलू उपकरण जैसी श्रेणियां प्रमुख आकर्षण होंगी। साथ ही लाइव ट्रेड डेमो भी दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहेंगे।मेले के दौरान युवाओं के लिए सीवी मेकिंग, इंटरव्यू स्किल्स, स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी ग्रूमिंग जैसे विषयों पर सॉफ्ट स्किल वर्कशॉप्स भी आयोजित की जाएंगी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी विशेष आयोजन होगा, जिससे युवाओं को प्रेरणा और मनोरंजन दोनों मिलेगा।राज्य के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के सर्वश्रेष्ठ उत्पादों का मंडलवार प्रदर्शन किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक बैठक

लखनऊ, । उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को गति देने और निर्यात संवर्धन की दिशा में उठाए जा रहे कदमों के तहत बुधवार को उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, लखनऊ में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उत्तर प्रदेश शासन के उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अपर मुख्य सचिव बी.एल. मीणा ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के चेयरमैन अभिषेक देव उपस्थित रहे।इस बैठक में विभागीय अधिकारियों के साथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए उद्यमियों ने भाग लिया और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पादों के देश–विदेश में निर्यात के दौरान आ रही चुनौतियों और समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की। उद्यमियों ने बताया कि यूरोपीय देशों, खाड़ी देशों और अमेरिका जैसे बाजारों में अलग–अलग खाद्य मानकों की जानकारी के अभाव में कई बार उत्पादों के निर्यात में अड़चनें आती हैं। इस पर अपर मुख्य सचिव बी.एल. मीणा ने एपीडा चेयरमैन से आग्रह किया कि तकनीकी जानकारी और निर्यात मार्गदर्शन हेतु एक तकनीकी सलाहकार की तैनाती उद्यान विभाग में की जाए, जिससे उद्यमियों को नियमित रूप से आवश्यक सूचनाएं प्राप्त हो सकें।बैठक में उप निदेशक (खाद्य प्रसंस्करण) द्वारा राज्य की नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति–2023 के तहत दी जा रही सुविधाओं और विशेष रूप से निर्यात प्रोत्साहन अनुदान के बारे में भी जानकारी दी गई।

मेक इन इंडिया के तहत 'द गोट ट्रस्ट' देगा युवाओं को पशुपालन का व्यावसायिक प्रशिक्षण, 18 राज्यों में संचालित है कौशल कार्यक्रम

लखनऊ, । केंद्र सरकार की मेक इन इंडिया योजना को जमीन पर उतारते हुए युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में 'अंतर्राष्ट्रीय बकरी प्रबंधन संस्थान–द गोट ट्रस्ट' द्वारा एक बड़ी पहल की गई है। राजधानी लखनऊ के रसूलपुर सदात स्थित संस्थान परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्थान के निदेशक प्रो. संजीव कुमार ने बताया कि 'द गोट ट्रस्ट कौशल संस्थान' युवाओं को पशुपालन में एक से तीन वर्ष तक का प्रशिक्षण देगा, जिसके पश्चात उन्हें स्थायी रोजगार का अवसर भी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।प्रो. कुमार ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को पशु चिकित्सा, चारा प्रबंधन, औषधि उपयोग, लैब संचालन, पशु देखभाल, तथा पशुपालन से जुड़े सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें कंप्यूटर विज्ञान, कृषि विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में भी तीन से छह माह की अवधि के कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देशभर में सफलतापूर्वक चल रहा है और वर्तमान में भारत के 18 राज्यों में संस्था के 8 प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं।उन्होंने बताया कि संस्था के "वी–वॉक" पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को तकनीकी और उद्यमिता के समन्वय से आत्मनिर्भर बनने का मार्ग दिखाया जाता है।इस कोर्स का उद्देश्य केवल तकनीकी प्रशिक्षण देना नहीं है, बल्कि युवाओं में व्यावसायिक सोच, आत्मसम्मान और सामाजिक भागीदारी का भाव भी विकसित करना है।प्रो. संजीव कुमार ने यह भी कहा कि संस्थान का लक्ष्य ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित करना है जो ग्रामीण और अर्ध–शहरी क्षेत्रों से आते हैं और अपने संसाधनों के माध्यम से स्वरोजगार की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। पशुपालन से जुड़े प्राकृतिक और आर्थिक लाभों को बताते हुए उन्होंने कहा कि यह न केवल स्वास्थ्यप्रद बल्कि कम निवेश में अधिक लाभ वाला व्यवसाय है।इस अवसर पर मौजूद डॉ. आशीष कुमार, डॉ. पंकज यादव, विनय गौतम और सौरभ गौतम ने भी पशुपालन, स्वास्थ्य सेवाओं और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक संभावनाओं पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे यह क्षेत्र युवाओं के लिए भविष्य का मजबूत आधार बन सकता है।

लखनऊ में पहली बार युवा कौशल चौपाल का आयोजन आत्मनिर्भर युवाओं की सफलता की गूंज से गूंजेगा मंच

लखनऊ, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश की राजधानी इस बार विश्व युवा कौशल दिवस (15 जुलाई) को एक ऐतिहासिक आयोजन का साक्षी बनने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'कौशल भारत – महाशक्ति भारत' संकल्प और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में पहली बार "युवा कौशल चौपाल"का आयोजन किया जा रहा है। 15 और 16 जुलाई 2025 को दो दिवसीय इस आयोजन में वह युवा अपनी प्रेरणादायक कहानियाँ साझा करेंगे, जिन्होंने कौशल प्रशिक्षण के जरिये न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी रोजगार का जरिया बने।इस विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (न्बैक्ड) से प्रशिक्षित सैकड़ों युवा शामिल होंगे, लेकिन मंच पर स्थान मिलेगा उन 11 चुनिंदा युवाओं को, जो आज कौशल के बलबूते अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। ये युवा 'कौशल यूथ आइकॉन' के रूप में सम्मानित किए जाएंगे।राज्य के कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने कहा, "यह आयोजन सिर्फ कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक युवा प्रेरणा आंदोलन होगा। यह मंच स्किल इंडिया के विजन को जन–जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगा। इससे हर गांव–कस्बे के युवा को यह संदेश मिलेगा कि कौशल ही असली ताकत है, जिससे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा जा सकता है।"उन्होंने आगे बताया कि इन युवाओं की सफलता की कहानियांकुछने मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर की शुरुआत, कहीं ब्यूटी पार्लर, डिजिटल स्टूडियो, होटल में रोजगार या खुद की कैफे चेन का संचालनकुआम बेरोजगारों के लिए प्रेरणा बनेंगी।मिशन निदेशक पुलकित खरे ने बताया कि इन 11 वक्ताओं का चयन पिछले तीन वर्षों में मिशन से प्रशिक्षण प्राप्त कर सेवायोजित हजारों युवाओं में से किया गया है। ये युवा चौपाल में अपने जीवन की यात्रा, संघर्ष और सफलता की कहानी साझा करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य कौशल आधारित सफलता की सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ाना और युवाओं के आत्मविश्वास को मजबूती देना है।कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी युवा न केवल कौशल के महत्व को समझेंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि कैसे प्रशिक्षण लेकर वे भी आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आयोजन के जरिये सरकार यह संदेश भी दे रही है कि बेरोजगारी का समाधान नौकरी ढूंढने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की क्षमता और कौशल को पहचानने में है।युवा कौशल चौपाल' के माध्यम से लखनऊ एक नई शुरुआत का गवाह बनेगा।कहानियाँ नायक वे होंगे, जो कभी संघर्ष कर रहे थे और आज दूसरों की जिंदगी बदल रहे हैं।

बीटेक प्रवेश की नई व्यवस्था शुरू, 122 सीटों पर जेईई मेंस से मिलेगा प्रवेश

गोरखपुर, संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में सत्र 2025–26 में बीटेक में प्रवेश प्रक्रिया में इस बार बदलाव किया गया है। इस वर्ष से जेईई मेन के स्कोर के आधार पर सीधे दाखिले की शुरुआत कर दी है। पहली बार डीडीयू ने बीटेक की कुल 600 सीटों में से 20 प्रतिशत यानी 122 सीटें जेईई मेन के आधार पर भरने की व्यवस्था लागू की है। डीडीयू में अब तक बीटेक में 50 प्रतिशत सीटों पर विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और 50 प्रतिशत सीटों पर यूपीटीयू (एकेटीयू) के माध्यम से दाखिला होता था। इस बार इसमें बदलाव करते हुए 50 प्रतिशत सीटें डीडीयू की प्रवेश परीक्षा, 30 प्रतिशत एकेटीयू के स्टेट काउंसिलिंग और शेष 20 प्रतिशत सीटें जेईई मेन के अंकों के आधार पर किए जाने का निर्णय लिया गया है। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा ने बताया कि जेईई मेन कोटे के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और इसके लिए अभ्यर्थी 18 जुलाई तक विश्वविद्यालय के पोर्टल www-dduguadmission-in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बीटेक में कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग और आईटी में 1505150 सीटें हैं, जिनमें 30–30 सीटें जेईई मेन कोटे के तहत भरी जाएंगी। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की 75–75 सीटों में से प्रत्येक के 16 सीटें जेईई मेन कोटे से भरी जाएंगी। प्रो. हर्ष सिन्हा ने बताया कि बीटेक की 50 प्रतिशत सीटों के लिए विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई को आयोजित की जाएगी। साथ ही बीटेक और बीफार्म द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी 18 जुलाई तय है।

बीएससी बायोलॉजी में कड़ी प्रतिस्पर्धा, एक सीट पर 23 अभ्यर्थी

गोरखपुर, संवाददाता। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स और एमएससी कृषि विज्ञान की प्रवेश परीक्षा हुईं। बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स की प्रवेश परीक्षा में हर एक सीट के लिए 23 अभ्यर्थियों के बीच मुकाबला रहा। दिलचस्प बात यह रही कि कुल आवेदकों में 76 प्रतिशत महिला अभ्यर्थी रहीं। प्रवेश प्रकोष्ठ के निदेशक प्रो. हर्ष सिन्हा ने बताया कि बीएससी बायोलॉजी ऑनर्स की परीक्षा विश्वविद्यालय के 7 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस परीक्षा में कुल 3386 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 2578 महिला और शेष पुरुष अभ्यर्थी थे। परीक्षा में कुल 2856 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। शाम की पाली में एमएससी एग्रीकल्चर विषय की परीक्षा में कुल 503 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 471 उपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान कुलपति प्रो. पूनम टंडन ने विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और अभ्यर्थियों से संवाद भी किया। उन्होंने परीक्षा व्यवस्था, प्रश्नपत्र की गुणवत्ता और समग्र अनुभव के बारे में अभ्यर्थियों से फीडबैक लिया। शुक्रवार को पहली पाली में बीकॉम ऑनर्स की परीक्षा दीक्षा भवन, मजीठिया भवन, वाणिज्य संकाय और लॉ फैकल्टी में आयोजित की जाएगी, जिसमें 2271 अभ्यर्थी शामिल होंगे। दूसरी पाली में एमएससी जूलॉजी की परीक्षा दीक्षा भवन में होगी, इसमें 850 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।

तीसरे राउंड में भी हाई रही मेरिट, अब चौथे चरण से आस

गोरखपुर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बीटेक के तीसरे चरण की काउंसिलिंग के लिए बृहस्पतिवार को कटऑफ सूची जारी हो गई। बृहस्पतिवार को ही काउंसिलिंग भी शुरू हो गई। काउंसिलिंग 12 जुलाई तक चलेगी। तीसरी सूची में भी लोकप्रिय विषयों में जेईई मेन के रैंक होल्डर्स को जगह मिली है। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि चौथे चरण की काउंसिलिंग में मेरिट नीचे पहुंचेगी और ज्यादा विद्यार्थियों को प्रवेश की राह खुलेगी। एमएमएमयूटी के डीन यूजी व प्रवेश समन्वयक प्रो. वीके मिश्र ने बताया कि बीटेक में दो चरणों की काउंसिलिंग में कुल 1189 में से 933 सीटें भर चुकी हैं। शेष 256 सीटों पर प्रवेश के लिए तीसरे राउंड की काउंसिलिंग शुरू हो गई है। अब तक प्रवेश ले चुके सभी विद्यार्थियों को अपनी पूरी फीस 15 जुलाई तक जमा करनी होगी। पूरा शुल्क जमा न करने वाले छात्रों का प्रवेश अपने आप निरस्त हो जाएगा। चौथे चरण के लिए सीट अलॉटमेंट व काउंसिलिंग 18 जुलाई से शुरू होगी। तीसरे चरण में भी उम्मीद के अनुरूप कंप्यूटर साइंस, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स में मेरिट एक लाख के अंदर ही है। कोर ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल के साथ ही केमिकल इंजीनियिरिंग में कटऑफ जेईई मेन के एक लाख रैंक से अधिक पर खुला है। बीटेक के लोकप्रिय पाठ्यक्रमों के लिए बड़ी संख्या में जेईई मेन में अच्छी रैंक पाने वाले अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। विभिन्न रैंकिंग में स्थान बनाने के कारण मेधावी छात्रों का भरोसा विश्वविद्यालय पर बढ़ा है।

सीडीओ ने विकास भवन में मारा छापा, 12 कर्मचारी मिले अनुपस्थित, एक दिन का रोका वेतन

गोरखपुर, संवाददाता। सीडीओ शाश्वत त्रिपुरारी ने शुक्रवार को सुबह विकास भवन में मौजूद कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में 12 कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए। सभी 12 कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोका गया है। साथ ही स्पष्टीकरण भी मांगा है। उधर, सीडीओ ने आईजीआरएस पोर्टल की भी जांच की। जांच में जीओ का उलंघन पाया गया। अधिकारी कई शिकायतों का निस्तारण न कर क्लोज रिपोर्ट लगा कर, शासन को शिकायत ट्रांसफर कर रहे थे। साथ ही मुख्यमंत्री पोर्टल की शिकायत का भी ये ही हाल था। इस पर कई विभागों के विभागाध्यक्ष का स्पष्टीकरण किया गया है।

नवजात के शव को नोच रहे थे कुत्ते, सड़क किनारे पड़ा मिला, अनचाहे गर्भ के बाद मासूम को फेंके जाने की आशंका

गोरखपुर, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र के हाटा बाजार में सर्विस लेन किनारे नाले पर शुक्रवार तड़के सुबह एक नवजात का शव मिला, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। नजर पड़ने पर राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। नवजात को किसने फेंका, इसकी जांच पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से शुरू कर दी है। घटना के बाद तरह–तरह की चर्चा है। जानकारी के मुताबकि, शुक्रवार सुबह हाटा बाजार में गोरखपुर वाराणसी हाइवे की सर्विस लेन के बगल में बने नाले पर नवजात के शव को कुत्तों का झुंड नोच रहा था। आसपास टहल रहे लोगों की नजर पड़ी। जानकारी होते ही आसपास के लोग भी एकत्र हो गए। पुलिस को इसकी जानकारी देते हुए लोगों ने कुत्तों को भगाया। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस को हाटा बाजार निवासी ताहिर अंसारी ने तहरीर देकर बताया कि सुबह 6 बजे उनके घर के सामने अज्ञात नवजात के शव को कुत्ते नोच रहे थे। एसओ सुशील कुमार चौरसिया का कहना है की प्रथम दृष्टया बच्चे को जन्म देने के बाद शव को फेंका गया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। एसपी देहात जितेंद्र तोमर ने बताया कि मौत की वजह जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पुलिस सीसीटीवी कैमरों और दूसरे स्रोतों से यह जानकारी करने की कोशिश कर रही है कि शव को किसने लाकर फेंका है। आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी।

कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढीले तारों को बिजली निगम कर रहा ठीक

गोरखपुर, संवाददाता। सावन माह के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के साथ ही श्रद्धालुओं की बिजली से सुरक्षा को लेकर बिजली निगम ने तैयारियां पूरी कर ली है। बिजली निगम ने जिले के 22 प्रमुख शिव मंदिरों और कांवड़ यात्रा के लिए छह प्रमुख मार्गों को चिह्नित किया है। इन सभी स्थानों और मार्गों के ढीले तारों की समुचित सैगिंग के साथ ही जर्जर तारों को बदलने तथा आवश्यकतानुसार विद्युत लाइनों की गार्डिंग की व्यवस्था की गई है। बिजली निगम ने जिले के छह प्रमुख मार्गों को चिह्नित कर सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। इन मार्गों पर स्थापित पोल, डबल पोल तथा स्टे वायर पर 50 माइक्रोन से अधिक मोटाई वाली पॉलिथीन या इंसुलेटेड टेप से खंभों को भू–तल से आठ फीट ऊंचाई तक कवर करने के साथ ही मार्गों पर स्थापित ट्रांसफार्मरों की बांस–बल्ली से अस्थाई बैरिकेडिंग कराई गई है। इसके अलावा ढीले एलटी व एचटी लाइनों के तारों की उचित सैगिंग का कार्य भी कराया गया है। कांवड़ यात्रा मार्गों और प्रमुख मंदिरों के आस–पास के बिजली खंभों और ट्रांसफार्मरों को कवर करने के साथ अन्य सुरक्षा कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इससे श्रद्धालुओं को परेशानी नहीं होगी।

संक्षिप्त खबरें

'14 जुलाई को होगा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन'

'रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'हरदोई' उपायुक्त उद्योग हर्ष प्रताप सिंह ने बताया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के कियान्वयन के सम्बंध में 14 जुलाई 2025 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन प्रातः 10 बजे से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरदोई में किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम पाली में विश्वविद्यालयोंध्डिग्री कॉलेजोध्इंजीनियरिंग कालेजोंध स्टार्ट–अप इन्क्यूवेशन केन्द्रोंध्आई०टी०आई०ध् पालीटेक्निक अदि के अन्तिम वर्षध्पास आउट छात्रोंध्अन्य सम्भावित लाभार्थियों के मध्य योजना का प्रस्तुतीकरण करते हुये अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को सी०एम०युवा से जोड़ने की कार्यवाही की जानकारी उपलब्ध करायी जायेगी। द्वितीय पाली में अपरान्ह 2.00 बजे से समस्त बैंकों के शाखा प्रबन्धकोंध्जिला समन्वयकोंध्अग्रणी जिला प्रबंधकध्सी०एस०सी० केन्द्रों के संचालकोंध्प्रशिक्षणदायी संस्थानों यथा–आरसेटी, कौशल विकास मिशन आदि के लाभार्थियों के मध्य योजना का प्रस्तुतीकरण करते हुये अधिक से अधिक शिक्षित युवाओं को सी०एम०युवा से जोड़ने के सम्बंध में कार्यशाला में योजनाध्पोर्टल आदि पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण व जिले हेतु 70–80 इनोवेटिव बिजनेस परियोजनाओं बिजनेंस ऑन व्हील्सध्फैचाइजी बिजनेस के सम्बंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।

पुरस्कार घोषित 48 अपराधी गिरफ्तार, 22 की खोली गई हिस्ट्रीशीट

बस्ती, (संवाददाता)। अपराध पर सख्ती बरतने के साथ जनपद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न मामलों में वांछित 48 इनामी अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेज दिया है। 22 आदतन अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। इस आपरेशन को जिलेभर में एक साथ चलाया गया, जिसमें थानों की पुलिस,क्राइम ब्रांच और स्पेशल टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की है। एक जनवरी 2025 से लेकर 30 जून 2825 तक कुल 20799 लोगों पर पुलिस ने निरोधात्मक कार्रवाई की है। गिरफ्तार किए अपराधियों पर लूट, हत्या, रंगदारी, गो तस्करी और महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले दर्ज थे। 10,000 से लेकर 50,000 रुपये तक के इनाम घोषित 48 अपराधियों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा गया है। पुलिस को यह सफलता मुखबिर तंत्र, सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रानिक सर्विलांस की मदद से मिली है। आगामी पंचायत चुनाव के मद्देनजर जनपद में अपराध नियंत्रण के लिए विशेष पहल की गई है। इसके लिए अपराध में संलिप्त लोगों को उन्होंने कुंडली खंगालना शुरू किया है। इनमें गंभीर मामलों में जमानत पर छूटे आरोपित शामिल हैं। अपराध में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से शामिल ऐसे आरोपितों को दुराचारी घोषित करके उन पर नकेल कसी जा रही है। लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पांच या पांच से अधिक अपराध करने वाले आदतन अपराधी पाए गए जनपद 22 लोगों की हिस्ट्रीशीट (आपराधिक रिकार्ड) खोली गई है, वे सभी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं और बार–बार अपराध में लिप्त पाए गए हैं। पुलिस की ओर से अब इनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। समय–समय पर इनके पते ठिकाने का सत्यापन भी किया जाएगा।

संक्षिप्त खबरें

जलाए गए निष्प्रयोज्य घोषित 13.52 करोड़ के स्टांप

बस्ती, (संवाददाता)। शासन से जनपद में निष्प्रयोज्य घोषित किए गए 13 करोड़ 52 लाख 25 हजार रुपये के स्टांप पेपर को छह सदस्यीय कमेटी की निगरानी में जला दिया गया। जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की ओर गठित की छह सदस्यीय कमेटी में एडीएम प्रतिपाल सिंह चौहान, सीटाओ अशोक कुमार प्रजापति, एसडीएम राजेश यादव, सीओ सिटी सत्येन्द्र भूषण तिवारी, प्रभारी एआइजी जुबेर अहमद व मख्य अग्निशमन अधिकारी यतीन्द्र नाथ शामिल रहे। इनकी देखरेख में कोषागार से स्टांप निकाल कर उसे जलाकर नष्ट कराया गया। सहायक महानिरीक्षक स्टांप देवेन्द्र कुमार ने बताया कि मार्च महीने में कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले के बाद दस हजार और उससे ज्यादा कीमत के स्टांप को पहले निष्प्रयोज्य घोषित कर दिया गया। उसके बाद नष्ट करने का आदेश दिया गया था। दस से 25 हजार रुपये की कीमत के 13 करोड़ 52 लाख 25 हजार रुपये मूल्य के स्टांप पेपर को चलन से बाहर कर दिया था। इसके बाद उन्हें अलग रख दिया गया था। एडीएम एफआर के नेतृत्व में चलन से बाहर होने वाले स्टांप को जलाकर नष्ट कर दिया गया।

देवेन्द्र कुमार सहायक महानिरीक्षक निबंधन, बस्ती

बस्ती, (संवाददाता)। पुरानी रंजिश को लेकर दंपती पर हमला कर उनका सिर फोड़ देने का मामला सामने आया है। पीड़ित राजेश कुमार निवासी ग्राम कड़र खास थाना पुरानी बस्ती ने अपनी तहरीर में बताया कि वह पत्नी को लेकर ससुराल से वापस आ रहा था कि मुंडेरवा के उमरी अहरा तिराहे पर पुरानी रंजिस को लेकर उनके व पत्नी पर अभिषेक, रामानंद निवासी चमरसन, थाना कोतवाली खलीलाबाद, संतकबीरनगर व दो अन्य लोगों ने एक राय होकर हमला बोल दिया गया। थानाध्यक्ष अतुल कुमार अंजान ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपितों पर विधिक कार्रवाई के लिए इनके ठिकानों पर तलाश की जा रही है।

कांवड़ यात्रा में डीजे का मानक तय, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

बस्ती। जनपद में कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे के प्रयोग का मानक शासन की ओर से तय कर दिया गया है। मानक का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित डीजे संचालक पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को पुलिस लाइन सभागार डीजे संचालकों व उनके आपरेटरों के साथ मीटिंग कर पुलिस अधीक्षक अभिनन्दन ने सर्वोच्च न्यायालय आदेश और शासन की गाइड लाइन की जानकारी दी। कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान निर्धारित मानक का पूरी तरह से पालन करना होगा। किसी भी प्रकार की उत्तेजक, भड़काऊ या आपत्तिजनक उद्घोषणा पर प्रतिबंध रहेगा, नियमों का पालन न करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यात्रा के दौरान धार्मिक मर्यादा, सामाजिक समरसता एवं सौहार्द का पूर्ण पालन किया जाए। डीजे की ध्वनि सीमा, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुरूप होनी चाहिए। तेज आवाज, अश्लील गाने, उत्तेजक नारे वर्जित रहेंगे। डीजे की ऊंचाई अधिक नहीं होनी चाहिए।

सोने की दस चेन का गुच्छा लेकर युवक फरार, घटना सीसीटीवी में कैद

प्रयागराज, (संवाददाता)। नैनी थाना क्षेत्र अंतर्गत एडीए मोड स्थित एक आभूषण की दुकान में शुक्रवार दोपहर को सोने की चेन खरीदने पहुंचा युवक चेन का गुच्छा लेकर फरार हो गया। युवक बीते तीन दिनों से दुकान में अपनी मां के लिए चेन खरीदने आ रहा था। शुक्रवार दोपहर को युवक आया था और पैसा लाने की बात कहकर चला गया था। दो घंटे बाद फिर से युवक पहुंचा और चेन लेने के दौरान चेन का गुच्छा लेकर फरार हो गया। गुच्छे में दस चेन थी, जिसकी कीमत नौ लाख बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेकर युवक की पहचान करने में जुटी है। जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के एडीए कालोनी निवासी राजेश वैश्य की एडीए मोड पर महालक्ष्मी ज्वैलर्स के नाम से आभूषण की दुकान है। शुक्रवार शाम करीब तीन बजे एक युवक दुकान पर सोने की चेन लेने पहुंचा था। उस समय दुकान में राजेश की पत्नी प्रीति मौजूद थी। युवक ने आठ से नौ ग्राम की चेन दिखाने की बात कही। प्रीति ने युवक को चेन दिखाई तो उसमें एक चेन पसंद कर वह उसकी कीमत पूछा। जैसे ही प्रीति चेन की तौल करने के लिए मुड़ी इतने में युवक चेन का गुच्छा लेकर दुकान से बाहर निकल गया। प्रीति शोर मचाते हुए दुकान से बाहर निकली, लेकिन तब तक युवक वहां से फरार हो गया। राजेश ने बताया कि युवक बीते तीन दिनों से लगातार अपनी मां के लिए चेन खरीदने के लिए आ रहा था। शुक्रवार दोपहर बारह बजे के आस–पास भी वह आया था। इसके बाद वह शाम को पहुंचा और घटना को अंजाम दे दिया। दुकानदार ने बताया कि गुच्छे में दस चेन थी, जिसका वजन अस्सी से नब्बे ग्राम था। इसकी कीमत लगभग नौ लाख रुपये थे। युवक द्वारा किया गया कृत्य दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं सूचना पर इंस्पेक्टर नैनी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल कर लौट आए। नैनी पुलिस दुकानदार को लेकर पुलिस लाइन पहुंच कर चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरा दिखाकर युवक की पहचान करने में जुटी है। इंस्पेक्टर नैनी बृज किशोर गौतम ने बताया कि युवक की पहचान व पकड़ने को लेकर टीम लगाई गई है। घटना के खुलासे के लिए एसओजी भी लगाई गई है। जल्द ही युवक को पकड़ लिया जाएगा।

विधान परिषद में उठेगा परिषदीय विद्यालयों को मर्जर किये जाने का मामला–देवेन्द्र प्रताप सिंह

बस्ती , (संवाददाता)। परिषदीय विद्यालयों को मर्जर किये जाने का आदेश वापस लिये जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक षिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल के नेतृत्व में संघ पदाधिकारियों, शिक्षकों ने विधान परिषद सदस्य देवेन्द्र प्रताप सिंह को न्याय मार्ग पर ज्ञापन सौंपा। मांग किया कि सरकार पर दबाव बनवाया जाय कि परिषदीय विद्यालयों को मर्जर किये जाने का आदेश वापस ले। देवेन्द्र प्रताप ने कहा कि इस मामले को सदन में पूरी मजबूती से उठाया जायेगा।ज्ञापन देने के बाद जिलाध्यक्ष उदयशंकर शुक्ल ने कहा कि परिषदीय विद्यालयों को बन्द कर अध्यापकों के पदों को समाप्त किया जा रहा है जिससे भविष्य में शिक्षकों की भर्ती न करनी पड़े। कहा कि सरकार के इस नीति से प्रदेश के कई जनपदों में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक सर प्लस होते जा रहे हैं। यह खतरनाक स्थिति है और आने वाली पीढी को शायद ही परिषदीय विद्यालयों में शिक्षक के रूप में अवसर मिले। ऐसे में बहुत जरूरी है कि सरकार विद्यालयों को बंद कर देने का अपना निर्णय वापस ले।यह जानकारी देते हुये जिला प्रवक्ता सूर्य प्रकाश शुक्ल ने बताया कि ज्ञापन सौंपने वालों में जिला मंत्री राघवेन्द्र सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार, कोषाध्यक्ष अभय सिंह यादव, मंजेश राजभर, रवि प्रताप सिंह, नवीन चौधरी, रवि प्रकाश शुक्ल, शिवम शुक्ल, रामपाल चौधरी, शारदा प्रसाद चौबे, शिवाकान्त पाण्डेय, रविशंकर शुक्ल, उमेश चन्द्र पाल, विनोद कुमार, अभिषेक उपाध्याय, कन्हैयालाल विश्वकर्मा, दीपक कुमार गौतम, ओम प्रकाश पाण्डेय, सुशील कुमार आजाद, मारूफ खान के साथ ही अनेक शिक्षक और संघ पदाधिकारियों के साथ ही एम.एल.सी. प्रतिनिधि हरीश सिंह शामिल रहे।

सावन शुरू होते ही सड़कों पर निकले कांवड़िए

प्रयागराज, (संवाददाता)। सावन के पहले ही दिन प्रयागराज में कांवड़ यात्रा का शुभारंभ भी हो गया। संगम तट पर स्थित दशाश्वमेध घाट इस दौरान सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले स्थानों में शामिल होता है। यहां हजारों कांवड़िये गंगा में स्नान कर पवित्र जल भरते हैं और ष्बोल बमष् के जयघोष के साथ काशी विश्वनाथ की ओर प्रस्थान करते हैं। कांवड़ियों की टोलियाँ भगवा वस्त्रों में लिपटी, हाथों में गंगाजल लिए, भक्ति के रंग में रंगी हुई नजर आ रही हैं। पूरा वातावरण ष्हर–हर महादेवष् और ष्बोल बमष् के नारों से गुंजायमान हो उठा है। सावन भर यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, जहां हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु जल भरने और भगवान शिव को अर्पित करने के लिए पहुंचेंगे। प्रशासन की ओर से घाटों और प्रमुख शिवालयों पर विशेष सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

गुरु पूर्णिमा पर महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी ने की माता–पिता की पूजा

प्रयागराज, (संवाददाता)। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर श्री हरिधाम बाबा सेवा समिति, गोठी बेलसारा प्रयागराज के पीठाधीश्वर परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विनयानंद गिरी जी महाराज द्वारा श्रद्धा–भक्ति और पर्यावरण संरक्षण का अद्वितीय संगम देखने को मिला। महाराज श्री ने सबसे पहले अपने माता–पिता की विधिवत पूजा–अर्चना कर यह संदेश दिया कि जीवन में सबसे पहले माता–पिता ही हमारे प्रथम गुरु होते हैं। इसके बाद, भक्तों द्वारा स्वामी विनयानंद गिरी जी की गुरु रूप में पूजा की गई और उन्होंने सभी शिष्यों को गुरु दक्षिणा के रूप में ष्माँ के नाम एक वृक्षष् लगाने का संकल्प कराया। इस अवसर पर प्रत्येक भक्त को महाराज जी ने एक–एक वृक्ष भेंट स्वरूप प्रदान किया और अपने आश्रम परिसर में भी वृक्षारोपण कर पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि गुरु–शिष्य परंपरा भारतीय संस्कृति की आत्मा है लेकिन सबसे पहले अपने जीवन के वास्तविक गुरुओं, अपने माता–पिता की पूजा करें। यही सनातन की जड़ है। जितना जरूरी जल को बचाना है, उतना ही जरूरी वृक्ष लगाना और उन्हें बचाना भी है। इस कार्यक्रम में समिति के वरिष्ठ पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति भी रही। कार्यक्रम में वरिष्ठ सचिव अमृतलाल विश्वकर्मा, सचिव गौरव श्रीवास्तव, प्रभारी सचिव रविन्द्र कुशवाहा, योगेश शर्मा, जयप्रकाश, विष्णु मोदनवाल, पुष्पेन्द्र कुशवाहा, संजय मोदनवाल, बबलू मोदनवाल, मंगल पटेल पत्रकार, शुशील यादव (पत्रकार) रोहित मोदनवाल, शिव बाबू पटेल, अनिल मौर्या, सुखदेव मोदनवाल, केशव मोदनवाल सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रद्धालु उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य केवल धार्मिक उत्सव ही नहीं बल्कि जन–जागरूकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को बढ़ावा देना भी था।

नितिन गड़करी से मिले बस्ती के श्रीकृष्ण, परिवहन, पर्यावरण, ग्रामोन्मुखी रोजगार पर चर्चा

बस्ती, (संवाददाता)। हर्रैया तहसील क्षेत्र के सिसई निवासी 'लोक भारती के राष्ट्रीय संपर्क प्रमुख श्रीकृष्ण चौधरी ने परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से शिष्टाचार भेंट कर पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक कृषि को लेकर वृहद चर्चा किया। यहां जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से श्रीकृष्ण चौधरी ने बताया कि परिवहन के साथ पर्यावरण एवं ग्रामोन्मुखी विषयों पर विचार–विमर्श हुआ। बैठक के दौरान नदी एवं जल संरक्षण, पर्यावरणीय सुधार, गौ आधारित प्राकृतिक कृषि तथा हरिशंकरी (पीपल, वटवृक्ष, पाकड़) वृक्ष रोपण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। इन विषयों को लेकर भविष्य की कार्ययोजना पर भी सहमति बनी। विशेष रूप से, राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरिशंकरी वृक्षों का रोपण एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) द्वारा किए जाने की योजना प्रस्तावित हुई है।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी मे. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक

श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव

मो0 – 7007415808, 9415034002

Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।